

स्वास्थ्य कर्मियों से अपेक्षा की कि वे ग्राम स्तर पर सक्रिय सहभागिता निभाते हुए हर गर्भवती महिला और बच्चे तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं तथा कुपोषित बच्चों को पहचान कर उन्हें आवश्यक उपचार दिलाएं।

उत्तेखनीय है कि प्रोजेक्ट संवर्धन अभियान के तहत जनपद के 300 पंचायत भवनों में विशेष वीएचएसएनडी सत्रों का आयोजन किया गया है, जिनका 300 अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण किया जा रहा है। इन सत्रों में स्वास्थ्य विभाग एवं आईसीडीएस विभाग के समन्वय से सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 'हर बच्चा स्वस्थ, हर माँ सुरक्षित' के लक्ष्य के साथ यह अभियान जनपद में पोषण सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

सफलता का अँधेरा: जब सब कुछ है, पर कुछ भी नहीं

[सफलता की असली परीक्षा: अकेलापन और रिस्ते]
[सच्ची सफलता: केवल ऊँचाई नहीं, साथ देने वाले हाथ]

सफलता, एक ऐसा शब्द जो सुनते ही आँखों में चमक भर देता है। मंच पर रोशनी, तालियों की गूँज, महँगी गाड़ियाँ, आलीशान घर और हर तरफ तारीफों की बारिश। समाज इसे केवल मुकाम नहीं, बल्कि मुकुट समझता है। जिसे यह मिल जाए, वही पूर्ण माना जाता है। लोग सफलता को सबसे बड़ी दौलत मानते हैं, और इसके लिए इंसान अपनी जिंदगी की हर छेटी खुशी को पीछे छोड़ देता है। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक अनकहा साया भी चलता है, जिसे बहुत कम लोग देखना चाहते हैं। सफलता की ऊँचाई पर पहुँचते ही इंसान एक अजीब खामोशी में खो जाता है। आवाजें दूर चली जाती हैं, हँसी फीकी पड़ जाती है, और भीतर एक ठंडी, सुनसान रात उतर आती है। यही वह क्षण है जब चमक के बीच अकेलेपन का अँधेरा धीरे-धीरे फैलने लगता है, और इंसान अपने भीतर की खोई हुई दुनिया से रूबरू होता है।

सोचिए उस व्यक्ति की कहानी जिसने अपने सपनों को सच करने के लिए खुद को भुला दिया। दिन काम में डूबे रहे, रात बेचैन रही, रिस्ते ‘कल’ पर टलते गए। परिवार पास था, पर दूरी महसूस होती रही; दोस्त साथ थे, पर उनकी बातें सुनी नहीं गईं। हर पल काम और लक्ष्य के लिए समर्पित रहा, और अपनी जरूरतों, अपनी भावनाओं, अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया। आज वही व्यक्ति सफलता की ऊँचाई पर है—नाम, दाम और पहचान सब उसके पास हैं। लेकिन जब दिन की रोशनी बुझती है, तो वह अपने ही घर में अजनबी बन



जाता है। फोन में अनगिनत नंबर हैं, लेकिन कोई नहीं जो दिल की हालत पूछे। सफलता ने उसे बहुत कुछ दिया, लेकिन बदले में उससे वह सब छीन लिया जो उसे इंसान बनाता था—वो अपनापन, वो सहजता, वो बिना शर्त की हँसी और रिश्तों की गर्माहत।

यह अकेलापन किसी विशेष पेशे या वर्ग तक सीमित नहीं है। पद पर चमकते सितारें, मैदान में जीतते खिलाड़ी, किताबों में अमर लेखक, या प्रयोगशालाओं में इतिहास रचते वैज्ञानिक— सभी इस सनगटे का सामना करते हैं। जब तालियाँ थम जाती हैं, कैमरे हट जाते हैं, तब बचता है सिर्फ एक इंसान और उसकी खामोशी। रिस्ते अब भावनाओं से नहीं, उपलब्धियों से जुड़े होते हैं। लोग साथ चलते हैं, लेकिन कदम सफलता के साथ मिलाते हैं, इंसान के साथ नहीं। जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती है, साथ चलने वाले कम होते जाते हैं। यादें बार-बार लौटती हैं—माँ की आवाज, दोस्तों की हँसी, बिना मतलब की बातों। सब कुछ है, लेकिन

वह अपनापन नहीं जो कभी बिना मांगे मिल जाता था। सफलता ने जीवन बड़ कर दिया, लेकिन दिल को छोटा और सूना छोड़ दिया।

समाज इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। हम मान लेते हैं कि जो सफल है, वह खुश होगा। उसकी थकान नहीं देखते, उसकी चुपी नहीं सुनते। पैसा सुविधा दे सकता है, सम्मान दिला सकता है, लेकिन किसी का इंतजार नहीं कर सकता, किसी के कंधे पर सिर रखकर रो नहीं सकता। जब इंसान जीवन के अंतिम मोड़ पर पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे उपलब्धियों से ज्यादा रिश्तों की कमी खलती है। तब एहसास होता है कि जीत सब कुछ नहीं होती; कुछ हारें ऐसी होती हैं जो जीवन भर चुभती रहती हैं। यही वह सच है जो समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। जीत को देखकर हम केवल चमक देखते हैं, पर उसकी असली कीमत और कीमत चुकाने वाला अकेलापन नहीं।

कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह आपकी सारी सफलता गायब हो जाए, तो क्या कोई ऐसा होगा जो फिर भी आपके पास बैठना चाहेगा? अगर उत्तर ‘हाँ’ है, तो आप सच में सफल हैं। और अगर ‘न’ है, तो समझ लीजिए कि आपने मंजिल तो पा ली, लेकिन रास्ते में

खुद को खो दिया। सफलता के पीछे नहीं, बल्कि सफलता के साथ चलना जरूरी है—रिश्तों को थामे हुए, अपनापन बनाए रखते हुए। जीवन की असली पहचान ऊँचाई नहीं, बल्कि वे हाथ हैं जो अँधेरे में भी आपका साथ नहीं छोड़ें। यही वह सफलता है जो दिल को भर देती है, और जीवन को वास्तविक अर्थ देती है। सफलता की चमक और अकेलेपन की खामोशी— ये दोनों जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। इसे समझना ही असली परिपक्वता है। जो व्यक्ति केवल मुकाम की ओर भागता है, वह कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। वही वास्तव में अमर बनता है, जो रिश्तों और अपनापन को साथ लेकर चलता है। सफलता केवल बाहरी दुनिया की मान्यता नहीं है; यह भीतर की संतुष्टि, आत्मीयता और उन रिश्तों में है, जो अँधेरे में भी आपका हाथ थामते हैं और आपका साथ नहीं छोड़ें। यही वह अनमोल सीख है, जिसे हर सच्चा सफल व्यक्ति अपने जीवन भर अपने साथ रखता है।

और सबसे अहम बात—सफलता की असली कसौटी यह नहीं कि आप कितनी ऊँचाई पर पहुँच गए, बल्कि यह कि मुश्किल समय में आपके साथ कौन खड़ा है। यही वह सच्चाई है, जिसे समझकर जीवन में स्थायित्व और सच्चा संतोष मिलता है। पैसा, शोहरत, नाम और सम्मान मायने रखते हैं, लेकिन वे अकेलेपन और दिल की खालीपन को नहीं भर सकते। इसलिए सफलता के साथ हमेशा उन लोगों को थामे रखें, जिन्होंने आपकी शुरुआत से ही आपका साथ दिया। यही वह अद्वितीय सफलता है, जो केवल आपकी चमक ही नहीं, बल्कि आपके दिल को भी रोशन करती है।

प्रो. आरके जैन

घुंघट हो या हिजाब गरिमा का सार्वजनिक उल्लंघन

भारतीय समाज में सदियों से महिलाओं अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए संघर्ष करती रही हैं। पितृसत्तात्मक समाज में उम्मीद थी कि अब महिलाओं को सम्मान मिलेगा, लेकिन हाल की घटना ने एक साथ कई प्रतिष्ठित पुरुषवादी चेहरों का सच उजागर कर दिया। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण के एक सरकारी कार्यक्रम में, जब नवनि्युक्त महिला डॉक्टर मंच पर अपना पत्र लेने आईं, तो नीतीश कुमार ने उनके चेहरे से हिजाब (या निफाब) खींचकर नीचे कर दिया। वीडियो में साफ दिखता है कि मंच पर मौजूद अन्य लोग, जिन्हें सभ्य कहा जाता है, हँसने लगते हैं। कुछ लोग इसे सुझा कारणों से जोड़कर बचाव कर रहे हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री शायद पहचान सत्यापित करना चाहते थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए किसी महिला की व्यक्तिगत पसंद और गरिमा का सार्वजनिक उल्लंघन जायज है?

कल्पना कीजिए, अगर उस महिला डॉक्टर की जगह मंच पर हँसने वाले पुरुषों की बेटी, बहू या पत्नी होती, तो क्या उन्हें हँसी आती?

शायद नहीं, क्योंकि वे अपनी महिलाओं की गरिमा समझते हैं। दूसरी कल्पना कीजिए: अगर महिलाओं से भरे मंच पर कोई महिला नेता पुरुष को सम्मान दे रही होती और इसी तरह का व्यवहार करती, तो क्या प्रतिक्रिया होती? सबसे पहले, यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री सचिवालय में था, जहाँ सुरक्षा की सख्त व्यवस्था होती है। नियुक्ति पत्र लेने वाले हर व्यक्ति की आईडी, नाम और फोटो पहले से सत्यापित होते हैं। महिला सुरक्षाकर्मी कपड़ों की जाँच करती हैं। अगर कोई खतरा होता, तो महिला को मंच पर पहुँचने ही नहीं दिया जाता। पहचान पुष्टि के लिए हिजाब हटाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें इशारे से या अलग से कहा जा सकता था। खुद हाथ बढ़कर खींचना बदतमीजी ही है।

दूसरे, यह महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकार का मामला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 14 सम्मान का अधिकार और अनुच्छेद 21 सम्मानजनक जीवन का अधिकार। घूँटट हो या हिजाब, महिला को छूना या खींचना अपराध है। सार्वजनिक मंच पर ऐसा व्यवहार निजता का हनन है।



तीसरे, सत्ता में बैठे व्यक्ति से अधिक संवेदनशीलता की उम्मीद होती है। नीतीश कुमार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। बिहार में लड़कियों की शिक्षा और साक्षरता योजना उनके क्रेडिट पर है। लेकिन यह घटना उन वचनों पर सवाल उठाती है। मंच पर हँसते लोग और मुख्यमंत्री का व्यवहार महिलाओं के प्रति पुरुषों की तुल्य सोच दर्शाता है। और तो और, एनडीए के एक सहयोगी मंत्री ने इस घटना पर बचाव करते हुए बेहद बर्तिया बयान दिया - ‘नकाब ही तो खींचा है, इतना हो गया... कहीं और रू देते तो क्या होता?’ यह बयान हंसेत हुए दिया गया, जो महिलाओं के प्रति घोर

असंवेदनशीलता और पुरुषवादी मानसिकता को पूरी तरह उजागर करता है। ऐसे शब्द न केवल अपमानजनक हैं, बल्कि समाज में महिलाओं की गरिमा को और कमजोर करते हैं। यह न केवल एक महिला का अपमान है, बल्कि पूरे समाज को गलत संदेश देता है। समाज में महिलाओं की गरिमा और स्वतंत्रता का सम्मान हर हाल में जरूरी है। सत्ता का दुरुपयोग कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। केवल तभी हम सचमुच एक सशक्त और समावेशी समाज की ओर बढ़ सकेंगे।

अम्बिका कुशवाहा ‘अम्बी’

सरकारी खजाने पर बोझ सांसद विधायकों के वेतन में भारी वृद्धि

एक समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री अपनी पत्नी लालता शास्त्री से अपनी धोती को पुनर्नी हो जाने पर तुरफाई करवा कर पहन लेते थे लेकिन देश के नागरिकों के टैक्स से आया धन का एक पैसा भी अपने फिजूलखर्ची के लिए लगा पाप समझते थे। इतना ही नहीं वह अपने कपड़े धोने में पैसे खर्च नहीं करते थे और किसी टयफ का निजी घरेलू काम काज में इस्तेमाल नहीं करते थे लेकिन आज हालात बदल चुके हैं हमारे जन प्रतिनिधि अपना अधिकार और हक मान कर सरकारी धन को खसोतेमें लगे हुए हैं अधिकधिकार वेतन बढ़िया यात्रा व दूसरे भत्ते और बिदेश यात्रा पर फिजूलखर्ची कर का में डूबते देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। पहले सेवा के लिए लोग गर्जनीति में आते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है समय बीतने के साथ-साथ आज हमारे जनप्रतिनिधि को कति सेवा की प्री कीमत वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण ओडिशा विधानसभा द्वारा पारित विधेयक है।

ओडिशा विधानसभा ने मंगलवार को अपने सदस्यों का मासिक वेतन तीन गुना से अधिक बढ़कर 1.11 लाख रुपये से 3.45 लाख रुपये कर दिया है, जो देश में जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले सबसे अधिक सैलरी स्ट्रक्चर में से एक होगा।

संसदीय कार्य मंत्री मुखेश महांलिंग ने बताया कि 17वीं वित्तिय बजट (जून 2024) से यह संशोधित वेतन प्रभावी होगा। इन संशोधनों के लिए सदन ने सर्वसम्मति से चार विधेयक पारित किए। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधायकों की पेंशन में भी लगभग तीन गुना वृद्धि की गई है। विधेयकों में यह भी प्रावधान है कि किसी भी वर्तमान विधायक की मृत्यु पर उसके परिवार को 25 लाख रुपये की सहयता राशि दी जाएगी। साथ ही हर पांच वर्ष में वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि का प्रावधान भी शामिल है। एक विधेयक यह भी अनुमति देता है कि भविष्य में ऐसी बड़ेतरि अर्थरादेश के माध्यम

से भी की जा सकेगी। इससे ओडिशा के विधायक देश में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बन जाएंगे। उन्हें मिलने वाली स्कम केरल, पंजाब, सिक्किम और गोवा के विधायकों के संयुक्त मासिक वेतन के बराबर और एक दर्जन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के दोगुना से अधिक हो जाएंगी। उनका मूल मासिक वेतन 35,000 रुपये से बढ़कर लगभग 90,000 रुपये हो जाएगा। पूर्व विधायकों को पेंशन के रूप में 1.20 लाख रुपये मिलने वाले हैं। 10 दिस्कर को राज्य विधान सभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री मुखेश महांलिंग ने कहा कि आठ साल के अंतराल के बाद हुई वेतन वृद्धि में मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को लिखे एक पत्र में विश्व के नेता नवीन पटनायक ने कहा कि वह अपने वेतन एवं भत्तों में हई वृद्धि ‘राज्य के गरीब लोगों के कल्याण के लिए’ छोड़ेंगे। गौरतलब है कि असम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू औरकश्मीर, राजस्थान और दिल्ली सहित कई राज्यों ने या तो समितियों का गठन किया है या विधायकों के वेतन बढ़ने के प्रस्ताव पेश किए हैं। गोवा जैसे कुछ राज्यों ने वेतन बढ़ाने से पहले किया है मगर भत्तों में जरूर इजाफा किया है। विशेषज्ञों ने कहा कि ओडिशा का फैसला इन राज्यों के लिए भी विधायकों का वेतन बढ़ने का रास्ता साफ कर सकता है।

अब आपको जानकारी देते हैं ओडिशा के बाद तेलंगाना (लगभग) 2 लाख रुपये), महाराष्ट्र (2.6 लाख रुपये), मणिपुर (2.5 लाख रुपये) और उत्तर प्रदेश (2.4 लाख रुपये) इसमें आगे हैं। उन राज्यों की विधान सभाओं में विधायक 2 लाख रुपये प्रति माह से अधिक वेतन लेते हैं जबकि 17 राज्यों में वेतन 1 से 2 लाख रुपये के बीच है। केरल के विधायकों का वेतन लगभग 70,000 रुपये प्रति माह है जो देश में सबसे कम है। इसके बाद पंजाब (84,000 रुपये) और सिक्किम, गोवा और दिल्ली आते हैं जहां वेतन 1 लाख रुपये से थोड़े कम है। प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से वेतन में यह बढ़ोतरी मेल नहीं खाती है। मसलन

ओडिशा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.6 लाख रुपये है जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा ऊपर है मगर राज्य बैंक में निचले पायदान पर है। सिक्किम देश का सबसे अमीर राज्य है जहां प्रति व्यक्ति आय लगभग 5.8 लाख रुपये है। वहां विधायकों को लगभग 90,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इस बैंक में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले गोवा और दिल्ली भी विधायकों को अधिक वेतन देने वालों में शुमार नहीं हैं वहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे गरीब राज्य विधायकों को अपेक्षाकृत अधिक वेतन देते हैं। महाराष्ट्र में विधायकों और अन्य माननीय पदाधिकारियों की सैलरी बढ़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकार ने उनके वेतन और भत्तों में बदलाव करने का फैसला लिया है, जिससे राज्य के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों की आय में बड़ इजाफा होगा।

महाराष्ट्र के विधायकों के वेतन में अब 60 हजार रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। पहले उन्हें जो वेतन मिल रहा था, उसमें बढ़ोतरी के बाद उनकी नई सैलरी 1 लाख 70 हजार रुपए प्रति माह हो जाएगी। यह बढ़ोतरी विधायकों को मिलने वाले वेतन, भत्तों और सुविधाओं को ध्यान में रखकर की गई है।

सरकार ने न केवल विधायकों की सैलरी बढ़ाई है, बल्कि पूर्व विधायकों के पेंशन भत्ते में भी वृद्धि की गई है। पहले उन् जो राशि मिलती थी, अब उसे बढ़कर 58 हजार रुपए प्रति माह करने पर सहमति बर चुकी है।

गौरतलब है कि विधायक उन विधेयकों पर मतदान करते हैं जो उनके वेतन-भत्तों में इजाफा करते हैं। यह कवायद अमूमन एक समिति की सिफारिशों के बाद शुरू हो जाती है। मूल वेतन के अलावा उन्हें कार्यालय और निर्वाचन क्षेत्र के खर्चों के लिए भत्ते, नि:शुल्क आवास सुविधा, यात्रा स्थितियों और वैक्कों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों के वेतन में मार्च में 24 प्रतिशत वृद्धि की गई जिससे 1 अप्रैल 2023 से उनका मासिक वेतन लगभग

1.24 लाख रुपये हो गया है। यह बढ़ोतरी वित्त अधिनियम, 2018 में पेश किए गए संशोधनों बाद हुआ जिनके तहत सांसदों के वेतन को लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के माध्यम से मुद्रास्फीति से जोड़ा गया और प्रत्येक पांच वर्षों में इसमें संशोधन अनिवार्य किया गया। लोकसभा के पूर्व सचिव पी डी आचार्य अनुसार विधायकों के वेतन के लिए कोई एक समान या अनिवार्य मानदंड नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद की तरह प्रत्येक विधान सभा के पास अपने सदस्यों के वेतन तय करने का अधिकार है। आम तौर पर थोड़ा बहुत विरोध होता है मगर ऐसे संशोधन सर्वसम्मति से पारित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय आर्थिक स्थितियों और व्यापक वेतन संरचनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। संसद हो या विधानसभाएं वहां मुद्दों को लेकर जब बहस या चर्चा शुरू होती है तो उस दौरान पक्ष और विपक्ष जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसको देखकर कई बार तो जनसाधारण भी

हर्षासार हो जाते हैं। लेकिन जब अपने वेतन और भत्ता को बढ़ाने का प्रस्ताव आये तो वह सर्वसम्मति से पारित होता है। यह बदलाव की बगर है जिसमें सेवा की कम और सुविधा व वेतन वसूली की भावना शीघ्र पर है अब देश के जनता से चुने नुमाइंदे घर फूंक तमाशा देखने का जोखिम नहीं उठते बल्कि सरकारी सुविधाओं का भरपूर दोहन कर अधिक सरकारी सुविधाओं का भरपूर दोहन कर अधिकारिक सुविधा व वित्तासपाएं वहां मुद्दों जीने की अपेक्षा रखते हैं वही येन-केन-प्रकरणे सात पीढ़ियों के लिए इराजान करने की जुगुप्सा में नैतिकता को तिलांजलि देने से भी नहीं चूक रहे हैं।

मनोज कुमार अग्रवाल

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस- संवैधानिक सुरक्षा से सामाजिक सद्भाव तक

लोकतंत्र की सक्षमता और उसकी परिपक्वता का सबसे सटीक पैमाना यह होता है कि वह अपने अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाने वाला अल्पसंख्यक अधिकार दिवस केवल एक वार्षिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह उस संकल्प को दोहराने का अवसर है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने आजादी की दहलीज पर लिया था। इसी दिन 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ‘अल्पसंख्यकों के अधिकारों की घोषणा’ को अंगीकार किया था, जिसने वैश्विक स्तर पर एक ऐसे मानक की आधारशिला रखी जहाँ बहुमत के शोर में अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान, भाषा और संस्कृति कहीं गुम न हो जाए।

भारत जैसे एक विशाल, बहुलवादी और बिविधतापूर्ण देश में इस दिवस की प्रासंगिकता और भी गहरी हो जाती है क्योंकि यहाँ का लोकतंत्र अपनी संस्थागत मजबूती के लिए नहीं, बल्कि अपनी समावेशी समावेशिता के लिए जाना जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय से ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा को एक वैकल्पिक उद्गता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक दायित्व के रूप में देखा गया। डॉ. बी.आर. अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने यह स्पष्ट समझा था कि एक वास्तविक लोकतंत्र केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने सबसे छोटे समुदायों को कितना सुरक्षित महसूस कराता है। इसी विजन का परिणाम है कि आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट लिपि, संस्कृति और भाषा के संरक्षण के साथ-साथ अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अटूट अधिकार देते हैं।

ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत ने 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित करके अपनी प्रतिबद्धता को कानूनी रूप दिया। 2004 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अलग से गठन होना इस दिशा में एक और बड़ा कदम था, जिसने योजनाओं को कागजों से निकालकर धरातल पर लाने का प्रयास किया। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों की विशिष्ट पहचान को सुरक्षित रखते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में जोड़ना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज जब हम इस दिवस को मनाते हैं, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि चुनौतियाँ केवल संवैधानिक ढांचों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं में भी समाया हुआ है। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर 68.5



प्रतिशत के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। इसी तरह आर्थिक भागीदारी के मोर्चे पर भी कई विसंगतियां नजर आती हैं। सच्चा समिति (2006) की रिपोर्ट ने अल्पसंख्यकों की, विशेषकर मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का जो खाला खींचा था, वह महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बना हुआ है। हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम और नई शिक्षा नीति के माध्यम से इन अंतरालों को पाटने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी एक लंबा सफर तय करना बाकी है।

भारत के अल्पसंख्यक समुदायों ने देश के गौरव में जो योगदान दिया है, वह अतुलनीय है। चाहे वह पारसी समुदाय का औद्योगिक योगदान हो, सिख समुदाय का शौर्य और सेवा भाव हो, या फिर ईसाई मिशनरियों द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया कार्य—इन सबके बिना आधुनिक भारत की कल्पना अधूरी है। लेकिन विकास के इस सफर में ‘डिजिटल डिवाइड’ और महामारी के बाद उत्पन्न हुई आर्थिक असमानता ने नई जटिलताएँ पैदा कर दी हैं। कोविड-19 के दौर में जिस तरह से हाशिए पर खड़े समुदायों के रोजगार और शिक्षा प्रभावित हुए, उसने हमें याद दिलाया कि समावेशी विकास के लिए केवल नीतियां पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उनके क्रियान्वयन में संवेदनशीलता और गति की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही, हाल के वर्षों में बढ़ते धार्मिक धुवीकरण और लिंचिंग जैसी घटनाओं ने एक असहज वातावरण सृजित किया है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव के ताने-बाने के लिए चिंता का विषय है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का वास्तविक महत्व तभी सार्थक होगा जब हम केवल प्रतीकात्मक समारोहों प्रकाशनों तक सीमित न रहकर, जमीनी स्तर पर एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करें।

वैश्विक संदर्भ में देखें तो अल्पसंख्यक अधिकार अब केवल किसी एक देश का आंतरिक मामला नहीं रह गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी 10) का उद्देश्य भी असमानता को कम करना है। भारत

ने हमेशा से ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के विचार को प्राथमिकता दी है, लेकिन इस वैश्विक छवि को बनाए रखने के लिए घरेलू स्तर पर आंतरिक सुझा और सामाजिक न्याय के पैमानों को और अधिक सख्त करना होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को अधिक स्वायत्तता और संसाधन प्रदान करना समय की मांग है। तर्कित वह केवल एक सलाहकार संस्था बनकर न रह जाए। इसके अलावा, डेटा की कमी एक बड़ी बाधा है, बिना सटीक और अद्यतन अल्पसंख्यक-विशिष्ट जनगणना के, कल्याणकारी योजनाओं का सटीक लक्ष्यीकरण असंभव है। आज के डिजिटल युग में शिकायत निवारण प्रणालियों को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाना अनिवार्य है, ताकि सुदूर इलाकों में बैठ कोई भी अल्पसंख्यक नागरिक अपने अधिकारों के हनन पर तुरंत आवाज उठा सके। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस वास्तव में बहुमत और अल्पमत के बीच एक स्वस्थ सेतु बनाने का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि एक सुदृढ़ राष्ट्र वहीं होता है जहाँ धर्मनिरपेक्षता केवल एक राजनीतिक नारा न होकर एक सामाजिक संस्कार हो। ‘सबका साथ, सबका विकास’ और ‘सबका विश्वास’ के नारे को चरितार्थ करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन समुदायों के भय को दूर करें जो स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। कौशल विकास, छात्रवृत्ति योजनाओं का बेहतर विस्तार और अंतर-धार्मिक संवाद के माध्यम से ही हम उस बहुलवादी समाज को बांध सकते हैं जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था।

अंततः, अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण कोई विशेष सुविधा नहीं है, बल्कि यह उस न्यायपूर्ण समाज की नींव है जहाँ पहचान को खतम नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक माना जाता है। भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, और इस शक्ति को सुरक्षित रखना हम प्रत्येक नागरिक का साझा दायित्व है। समावेशी भारत की ओर बढ़ते कदम ही हमारे लोकतंत्र को दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में पेश करेंगे।

महेन्द्र तिवारी

टूटती उम्मीदों का समाज और आत्महत्या का बढ़ता संकट, सभ्य समाज के लिए करुणाजनक स्थिति

स्कूल के बच्चों से लेकर सुझाबलों के जवानों तक आत्महत्या की घटनाएँ आज भारतीय समाज की सबसे पीड़ादायक और चिंताजनक सच्चाइयों में शामिल हो चुकी हैं। यह केवल किसी एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती बल्कि पूरे परिवार के लिए ऐसा कुटुम्बगत बन जाती है, जिसकी भरपाई जीवन भर नहीं हो पाती। हाल के वर्षों में सामने आए अनेक उदाहरण बताते हैं कि यह समस्या अब किसी एक वर्ग या आयु समूह तक सीमित नहीं रही, बल्कि किसानों, युवाओं, विचारित महिलाओं, कर्मचारियों और देश की सुझा में तैनात जवानों तक फैली हुई है।

‘गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते तीन वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 438 जवानों ने आत्महत्या की। हालाँकि संस्कार का कहना है कि आत्महत्या के मामलों में हाल के वर्षों में कमी आई है। 2023 में जहां 157 आत्महत्याएँ दर्ज की गई थीं, वहीं 2025 में यह संख्या पचास 133 रह गई। यह गिरावट रहत देने वाली एक संकेत है, लेकिन समस्या की गंभीरता को कम नहीं करती। इसके साथ ही 2014 के बाद से अब तक 23,360 जवानों द्वारा इस्तीफा दिया जाना यह संकेत देता है कि सुझाबलों के भीतर मानसिक दबाव, कार्यस्थल तनाव और पारिवारिक समस्याएं गहराई से मौजूद हैं।

इस्तीफों के आंकड़े भी चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। सबसे अधिक इस्तीफे सीमा सुझा बल और असम राइफल्स से जुड़े हैं। बीएसएफ में 7,493, सीआरपीएफ में 7,456 और सीआईएसएफ में 4,137 जवानों ने सेवा छोड़ी। केवल 2025 तक ही 3,077 इस्तीफे दर्ज किए गए जिनमें से 1,157 बीएसएफ से हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि अशुशासन, देरसाए और सम्मान के बावजूद जवान भी इंसान हैं, जिनकी भावनाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और मानसिक सीमाएँ होती हैं। लगातार तनावपूर्ण ड्यूटी, लंबी तैनाती, परिवार से दूरी और पड़ोसिता या छुट्टी से जुड़ी समस्याएं धीरे-धीरे उन्हें भीतर से तोड़ देती हैं।

आत्महत्या की समस्या केवल सुझाबलों तक भता को बढ़ने का प्रस्ताव आये तो वह सर्वसम्मति से पारित होता है। यह बदलाव की बगर है जिसमें सेवा की कम और सुविधा व वेतन वसूली की भावना शीघ्र पर है अब देश के जनता से चुने नुमाइंदे घर फूंक तमाशा देखने का जोखिम नहीं उठते बल्कि सरकारी सुविधाओं का भरपूर दोहन कर अधिकारिक सुविधा व वित्तासपाएं वहां मुद्दों जीने की अपेक्षा रखते हैं वही येन-केन-प्रकरणे सात पीढ़ियों के लिए इराजान करने की जुगुप्सा में नैतिकता को तिलांजलि देने से भी नहीं चूक रहे हैं।

वैवाहिक कलह, देहेज उपीड़न, घरेलू हिंसा, अवैध संबंधों का शक, तलाक की आशंका और सामाजिक दबाव कई लोगों को मानसिक रूप से इतना कमजोर बना देते हैं कि वे जीवन समाप्त करने जैसा कठोर कदम उठा लेते हैं।

महिलाओं के लिए यह दैर विशेष रूप से निराशाजनक बनता जा रहा है। पढ़े-लिखी और आत्मनिर्भर होने के बावजूद सामाजिक अपेक्षाएं, पारिवारिक दबाव और रिश्तों में सम्मान की कमी उन्हें भीतर से तोड़ देती है। कई मामलों में महिलाएँ लंबे समय तक मानसिक पीड़ा सहती रहती हैं, लेकिन समाज और परिवार उनकी वेदना को गंभीरता से नहीं लेता। जब कोई रस्ता नहीं दिखता, तब आत्महत्या उन्हें एकमात्र समाधान प्रतीत होने लगती है। इसे केवल व्यक्तिगत कमजोरी कहना नैतिक, कानूनी और संस्थागत विफलता को छिपाने जैसा है।

सबसे अधिक चिंता का विषय किसानोंवस्था में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति है। स्कूल जाने वाले बच्चे और टैक्सीर आज जितना मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं, वह पहले कभी इतना गहरा नहीं था। पढ़ाई में प्रतिस्पर्धा, परीक्षा में अच्छे अंकों लाने का दबाव, माता-पिता की अपेक्षाएं, प्रोफेशनल मांडीझ पर गहराई से मौजूद हैं।

इस्तीफों के आंकड़े भी चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। सबसे अधिक इस्तीफे सीमा सुझा बल और असम राइफल्स से जुड़े हैं। बीएसएफ में 7,493, सीआरपीएफ में 7,456 और सीआईएसएफ में 4,137 जवानों ने सेवा छोड़ी। केवल 2025 तक ही 3,077 इस्तीफे दर्ज किए गए जिनमें से 1,157 बीएसएफ से हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि अशुशासन, देरसाए और सम्मान के बावजूद जवान भी इंसान हैं, जिनकी भावनाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और मानसिक सीमाएँ होती हैं। लगातार तनावपूर्ण ड्यूटी, लंबी तैनाती, परिवार से दूरी और पड़ोसिता या छुट्टी से जुड़ी समस्याएं धीरे-धीरे उन्हें भीतर से तोड़ देती हैं।



लेकर अनिश्चितता प्रमुख कारण बनते हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए केवल कानून बनाना या आंकड़े पेश करना पर्याप्त नहीं है। जरूरत है लोगों के मन की वेदना को समझने की। परिवार को पहला सहारा बनना होगा। माता-पिता को बच्चों की उपलब्धियों के साथ-साथ उनकी असफलताओं को भी स्वीकार करना सीखना होगा। तुलना की जगह संवाद को महत्व देना होगा। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना जाना चाहिए ताकि बच्चे अपनी भावनाओं को पहचानना और व्यक्त करना सीख सकें।

सरकारी और निजी स्तर पर काउंसिलिंग सेवाओं को सुलभ और सामान्य बनाना समय की मांग है। सुझाबलों में नियमित मानसिक स्वास्थ्य जांच, तनाव प्रबंधन कार्यक्रम और परिवार से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील नीतियां अपनानी होंगी। जवानों को विशेषज्ञों के अंदर ही अंदर तोड़ रही है। इस उग्र में मस्तिष्क और भावनाएं दोनों विकास की अवस्था में होती हैं, इसलिए छोटी-छोटी असफलताएँ भी उन्हें जीवन की सबसे बड़ी हार लगने लगती हैं। कई विशेषज्ञ अपने माता-पिता से खुलकर बात नहीं कर पाते। डर रहता है कि डांट पड़ेगी, तुलना होगी या उनकी बातों को हल्के में लिया जाएगा। स्कूलों में काउंसिलिंग की व्यवस्था अब भी सीमित है और जहां है भी, वहां मानसिक स्वास्थ्य को लेकर छिद्रक बनी रहती है। परिणामस्वरूप बच्चे अपने दर्द को भीतर दबाते रहते हैं, जो किसी एक क्षण में विस्फोट बनकर आत्महत्या का कारण बन जाता है। आत्महत्या के कारणों पर गौर करें तो यह साफ दिखता है कि यह किसी एक वजह से नहीं होता। आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, कर्ज, पारिवारिक कलह, प्रेम संबंधों में असफलता, सामाजिक अपमान, अकेलापन, अस्वस्थ और नशे की लत जैसे कई कारण मिलकर व्यक्ति को इस अँधेरे रास्ते की ओर धकेलते हैं। विशेषज्ञों के मामलों में पहचान का संकट, अस्वीकृति का डर और भविष्य को

कांतिलाल मांडोट



धिकाारी ने की समीक्षा

कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा विचलन कदापि स्वीकार्य नहीं है। भविष्य में यदि कार्य प्रगति में अपेक्षित सुधार नहीं पाया गया तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध और भी कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि जनपद के समस्त संबंधित अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण संवेदनशीलता तत्परता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करेंगे, ताकि कोई भी पात्र नागरिक योजना के लाभ से वंचित न रहे।

संक्षिप्त खबरें

महर्षि मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन



नैनी, प्रयागराज बुधवार को महर्षि मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन आश्रम प्रभारी सुनील श्रीवास्तव और बसंत दास द्वारा किया गया। आश्रम प्रभारी बसंत दास, सुनील श्रीवास्तव ने बताया महर्षि महेश योगी आश्रम के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश वर्मा के निर्देशन में बुधवार से मैच का कार्यक्रम लगातार 30, 12 ,2000 25 तक चलेगा। फाइनल मैच तक क्रिकेटरों के द्वारा खेला जाएगा। आज का मैच टॉस के माध्यम से किया। जिसमें प्रथम प्रयागराज एवं उक्कल के बीच में मैच खेला जा रहा है। जिसके कप्तान अनिल शर्मा एवं उकर्ष उक्कल के कप्तान अनूप चौबे के बीच में आज मैच खेला गया। इस अवसर पर ऋषि त्रिवेदी, सोनू पांडे, प्रशांत दास, काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष सरदार पद्विंदर सिंह, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय श्रीवास्तव, सचिन रिछारिया अनुराग दुबे, अनूप चौबे, संजीव, सनल, अजय पांडा, राजेश पांडे, एवं सामाजिक कार्यकर्ता शाहनवाज खान, पार्षद मयंक यादव उत्साहवर्धन के लिए मौजूद थे।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व महापौर का जन्मदिन धूमधाम से मनाया



नैनी, प्रयागराज। भारतीय जनता पार्टी नैनी मंडल के द्वारा बुधवार को चाका घाट के चुंगी चौराहे पर पार्षद अनूप भारतीय के नेतृत्व में पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर के एक दूसरे को खिलाया। इस मौके पर मिठाई का भी वितरण किया गया।कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नैनी मंडल अध्यक्ष रजत दुबे, पूर्व मंडल अध्यक्ष दिलीप केसरवानी, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष नरसिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।समारोह का संचालन भाजपा के वरिष्ठ नेता धनश्याम जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में कुंदन सिंह,मनीष कुशवाहा, प्रहलाद सिंह तोमर, मोहम्मद यीशु, ताज खान, नरेंद्र भारतीय, लालमनी मिश्रा, अंकित गुप्ता, तमाम क्षेत्र के व्यापारी नागरिक उपस्थित थे।

महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित विषय पर कार्यशाला आयोजित



ब्यूरो प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे, मुख्यालय में रेलवे बोर्ड की जारी पत्र के अनुसार दिनांक 10.12.2025 से 17.12.2025 तक सेक्सुअल हैरैसमेंट प्रिवेंशन बोर्ड के अन्तर्गत दिनांक 17.12.2025 को सांयकाल 15:00 बजे से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉ. मंजू लता हाण्डू अपर मुख्य स्वास्थ्य निदेशक, डॉ. साधना श्रीवास्तव असि. प्रोफेसर, उ. प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविदद्यालय एवं श्रीमति गरिमा त्रिपाठी, उप मुख्य विवर सलाहकार मुख्यालय प्रयागराज के द्वारा व्यव्थान दिया गया। डॉ. मंजू लता हाण्डू के द्वारा कर्मचारियों को POSH Act 2013 के संबंध में अवगत एवं जागरूक कराया गया। इस अवसर पर इस संगोष्ठी में उत्तर मध्य रेलवे, मुख्यालय के सभी विभागों से महिला रेलकर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

हरियाणा एसटीएफ द्वारा बैंक खातों का दुरुपयोग मामले में छापेमारी, अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। कौंधियारा थाना क्षेत्र के गिंधौरा गांव में गरीब ग्रामीणों के बैंक खातों के दुरुपयोग से जुड़ा एक अंतरराज्यीय मामला सामने आया है।इस गंभीर प्रकरण की जांच के लिए देर रात हरियाणा की एसटीएफ टीम गिंधौरा गांव पहुंची।टीम ने मुख्य आरोपी उदित पांडेय उर्फ कान्हा के परिजनों से गहन पूछताछ की। एसटीएफ ने आरोपी की गतिविधियों, संपर्कों, बैंक लेनदेन और नेटवर्क से संबंधित अहम जानकारीयां जुटाने की कोशिश की।

हालांकि,ग्रामीणों के अनुसार मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही सभी नामजद आरोपी फरार चल रहे हैं।।आवश्यक सूचनाओं के अभाव में एसटीएफ टीम को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कौंधियारा पुलिस ने अब तक जांच के नाम पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। गिंधौरा गांव में वर्षों से एक सगंठित गिरोह सक्रिय था,जो गरीब महिलाओं और ग्रामीणों को बहला-



फुसलाकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाता था। इसके बाद गिरोह उनके एटीएम कार्ड, पासबुक और सिम कार्ड अपने कब्जे में लेकर इन खातों के माध्यम से संदिग्ध लेनदेन करता था।।आरोप हैकि इन खातों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय हवाला और बड़ी मात्रा में धनराशि की फंडिंग के लिए किया गया।।ग्रामीणों ने बताया कि जब खाते सीज हो जाते थे,तब पीड़ितों को मामूली कौंधियारा पुलिस ने अब तक जांच के नाम पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। गिंधौरा गांव में वर्षों से एक सगंठित गिरोह सक्रिय था,जो गरीब महिलाओं और ग्रामीणों को बहला-

माघ मेला 2026 की तैयारी में बाधा

● पाटून पुल नंबर-2 का काम ठप, मारपीट का आरोप



हो गया। घटना की सूचना मिलने पर माघ मेला प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। इस घटना से माघ मेला 2026 की तैयारियों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। जेसीबी ऑपरेटर ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मेला प्राधिकरण की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जबकि प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच की तैयारी की जा रही है।उल्लेखनीय है कि माघ मेला 2026 को लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क है, ऐसे में निर्माण कार्य के दौरान इस तरह के विवाद व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री निर्देश पर माघ मेले की तैयारियाँ जोरों पर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में सदी ने अपना पूरा असर दिखाया शुरू कर दिया है। तापमान में लगातार गिरावट और सुबह-शाम छाप घने कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। संगम क्षेत्र, मेला परिसर और प्रमुख मार्ग ठंड की चपेट में हैं, जिससे आवाजाही पर भी असर देखने को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन, मेला प्रशासन और संबंधित विभाग पूरी सक्रियता के साथ कार्य में जुटे हुए हैं। संगम तट पर मेला क्षेत्र का विस्तार,टेंट सिटी का

निर्माण, घाटों का सुदृढ़ीकरण, बिजली और पेयजल आपूर्ति, साफ- सफाई, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा कल्पवासियों और श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ठंड को देखते हुए मेला क्षेत्र में अलाव, रैन बसेरों, चिकित्सा शिविरों और एम्बुलेंस सेवाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की योजना पर भी कार्य चल रहा है।

यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र और शहर में निर्माण, घाटों का सुदृढ़ीकरण, बिजली और पेयजल आपूर्ति, साफ- सफाई, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा कल्पवासियों और श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ठंड को देखते हुए मेला क्षेत्र में अलाव, रैन बसेरों, चिकित्सा शिविरों और एम्बुलेंस सेवाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की योजना पर भी कार्य चल रहा है।

यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र और शहर में निर्माण, घाटों का सुदृढ़ीकरण, बिजली और पेयजल आपूर्ति, साफ- सफाई, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा कल्पवासियों और श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ठंड को देखते हुए मेला क्षेत्र में अलाव, रैन बसेरों, चिकित्सा शिविरों और एम्बुलेंस सेवाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की योजना पर भी कार्य चल रहा है।

भाजपा का बैनर फाड़ने से मना करने से युवक पर असलहे से फायर, मुकदमा दर्ज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महिलाबाद। भाजपा का बैनर फाड़े जाने तथा बैनरों को फाड़ने से मना करने से मनबढ़ों ने युवक पर प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया परजिन तुरंत सीएचसी ले गए जहाँ पर इलाज जारी है। अनुपम सिंह निवासी पुरवा ने तहरीर देते हुए बताया कि वह भाजपा कार्यकर्ता है पार्टी के बैनर ढेढेमऊ गांव में लगे हुए थे शाम को गोलू ब्लैक गाजी, दानिश और कामिल तथा आषा दर्जन अज्ञात लोग दबंगई के बल पर भाजपा के लगे हुए बैनर फाड़ने लगे जिसका अनुपम ने विरोध किया।तभी गोलू ब्लैक ने गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से अवैध असलहे से दो फायर कर दिए गोली अनुपम के बगल से निकल गई तो गोलू व

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

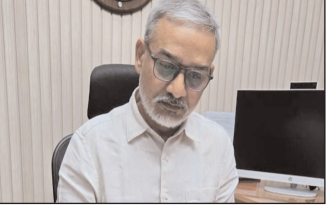
औरई विधानसभा क्षेत्र, जनपद भदोही में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के औरई तहसील महामंत्री नेहाल अली के नेतृत्व में पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण को लेकर माननीय विधायक दीनानाथ भास्कर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पंजीकृत पत्रकार संगठन है, जो प्रदेश के 18 मंडलों, 75 जनपदों एवं 551 तहसीलों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। बावजूद इसके, ग्रामीण

क्षेत्रों में कार्यरत प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को सरकारी सुविधाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से तहसील स्तर पर पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने, पत्रकार हितों की रक्षा हेतु स्थाई समितियों के गठन, ग्रामीण पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड एवं नि:शुल्क बस यात्रा सुविधा, प्रदेश स्तरीय मान्यता व विज्ञापन समितियों में प्रतिनिधित्व, लखनऊ में संगठन के लिए नि:शुल्क कार्यालय, ग्रामीण पत्रकार आयोग के गठन तथा पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज

प्रयागराज मंडल

UP बोर्ड इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी, दो चरणों में होगी परीक्षाएं

24 जनवरी से 9 फरवरी तक आयोजन, 29-30 जनवरी को UPTET के चलते रहेगा अवकाश।



ब्यूरो प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP बोर्ड) ने वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस वर्ष प्रयोगात्मक परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित की जाएंगी। पहले चरण में 24 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 तक 10 मंडलों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएंगी। इनमें आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल शामिल हैं।परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि 29 और 30 जनवरी 2026 को प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं होंगी। इन दोनों दिनों में यूपीटीईटी की लिखित परीक्षा आयोजित होने के कारण विद्यालयों में शैक्षिक अवकाश रहेगा। दूसरे चरण की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 2 फरवरी से 9 फरवरी 2026 के बीच संपन्न कराई जाएंगी। इस चरण में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल के विद्यालय शामिल होंगे। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने विज्ञप्ति जारी कर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

हण्डिया पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार



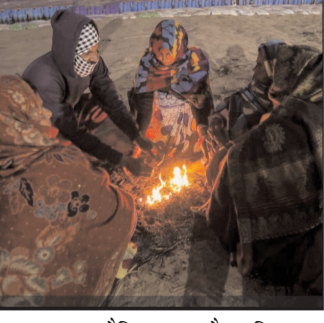
ब्यूरो प्रयागराज। थाना हण्डिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-689/25 धारा-137(2) भा0न्या0स0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बाबू लाल पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम सुथवै थाना ऊंच जनपद भदोही को थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-17.12.2025 को जनपद मिर्जापुर के थाना चील्ह क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चील्ह तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता,पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया तथा साक्ष्य संकलन एवं पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-87/64(2) भा0न्या0सं0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

करछना की रामकथा में उमड़ा भक्ति का सागर

● जानकी विदाई पर रो पड़ी मिथिला। वाणी और क्रोध पर संयम का दिव्य संदेश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

करछना, प्रयागराज। हिंदूपुर करछना में मिश्रा परिवार द्वारा आयोजित श्रीराम कथा के चौथे दिन पांडाल भक्ति, भाव और आस्था से सराबोर हो उठा। कथा वाचिका पूज्या शास्त्री शाकाम्भरी द्विवेदी मानस मंजरी ने भगवान परशुराम जी के जनकपुरी आगमन से लेकर श्री सीताराम विवाह की अनुपम कथा का ऐसा सजीव वर्णन किया कि श्रोता मानो स्वयं मिथिला के आंगन में उपस्थित हो गए। जैसे ही शिवधनुष भंग का प्रसंग आया, पांडाल 'जय श्रीराम' के जयकारों से गूंज उठा। भजनकों की मधुर धुनों पर भक्त झूम उठे और हर दिशा में भक्ति के रंग बिखर गए। शास्त्री जी ने भावविभोर स्वर में वर्णन किया कि किस प्रकार अयोध्या से



अलग-अलग ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रमुख स्नान पर्वों को ध्यान में रखते हुए भीड़ नियंत्रण, सीसीटीवी निगरानी और कंट्रोल रूम को और प्रभावी बनाया जा रहा है।

गेहूं की बुआई ठप, ज्ञानपुर एम्य केनाल में पानी छोड़ने को लेकर किसानों का प्रदर्शन भदोही। सीतामढ़ी डीघ ब्लॉक क्षेत्र के महादेवा गांव में किसानों ने सिंचाई संकट को लेकर नहर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि ज्ञानपुर पम्प केनाल में शीघ्र पानी छोड़ा जाए, ताकि गेहूं की बुआई समय पर पूरी हो सके। प्रदर्शन के दौरान समाजसेवी लालू यादव ने कहा कि इस समय रबी सीजन की सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं की बुआई चल रही है, लेकिन नहरों में पानी न होने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समय पर सिंचाई न होने से फसल प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है, जिससे किसानों में आक्रोश है। किसानों ने नहर विभाग से जल्द से जल्द केनाल में पानी छोड़ने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान शीघ्र नहीं हुआ तो आंदोलन की ओर तेज किया जाएगा। इस मौके पर राम गिरि, लवलेश यादव, सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

सीडीओ ने निर्माणाधीन कार्यों, सीएम डैश बोर्ड व आधार अनुश्रवण समिति की समीक्षा की

● सीएम डैश बोर्ड पर योजनाओं का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करते हुए प्रगति में सुधार लाये-सीडीओ

प्रतापगढ़। मुख्य विकास अधिकारी डा0 दिव्या मिश्रा की अध्यक्षता विकास भवन सभागार में जनपद में निर्माणाधीन कार्यों, सीएम डैश बोर्ड पर प्रदर्शित विकास कार्यों व आधार अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में शिक्षा विभाग से सम्बन्धित विकास खण्ड लक्ष्मणपुर में राजकीय डिग्री कॉलेज, यूपीएस केवराकला का अपग्रेडेशन, राजकीय पॉलिटेक्निक पट्टी, पुलिस विभाग सम्बन्धित बनवीरकाछ में नवीन थाना कोतवाली देहात के अनावासीय भवन हॉस्टल, बैंक एवं विवेचना कक्ष स्वास्थ्य विभाग के पीएचसी भदरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीगंज कैथोला आदि पूर्ण कार्यों को तत्काल प्रशासकीय विभाग को हस्तगत करने के निर्देश दिये गये। मुख्य विकास अधिकारी ने सीएम डैश बोर्ड पर प्रदर्शित विकास कार्यों से सम्बंधित योजनाओं,कार्यक्रमों की माह नवम्बर प्रगति के आधार पर योजनाओं,कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी। माह नवम्बर में सीएम डैश बोर्ड पर विकास कार्यों में जनपद को राज्य में 16

सीधटिकट गांव में 5 वर्षों से नहीं खुला शौचालय का ताला, ग्रामीणों ने उठाई आवाज



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज। बारा अंतर्गत विकासखंड शंकरगढ़ क्षेत्र के सीधटिकट गांव में वर्ष 2020 में 7 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक शौचालय आज तक चालू नहीं हो सका है।सरकारी अभिलेखों में इसे संचालित दिखाया गया है,जबकि हकीकत में इसका ताला 5 साल से नहीं खुला है।ग्रामीणों का कहना है, कि शौचालय बंद होने के कारण महिलाएं,बुजुर्ग और बच्चे खुले में शौच जाने को मजबूर हैं।इससे उनकी गरिमा और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।ग्रामीणों के अनुसार, शौचालय नियमित सफाई नहीं होती है,और ना ही पानी की व्यवस्था है।नल लगे होने के बावजूद उसमें से पानी नहीं आता। इस संबंध में ग्राम प्रधान सूरज सिंह ने बताया कि शौचालय की चाबी सफाईकर्मी जल्लाधी धरिकार को सौंपी गई है। उन्होंने कहा, कि शौचालय खोलने और साफ-सफाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उसी

की है।हालांकि, ग्रामीणों का दावा इससे भिन्न है। इंद्रदेव सिंह, गौतम सिंह, नरेंद्र, बनवारी, विकास और राकेश सिंह सहित कई अन्य ग्रामीणों ने बताया कि आज तक शौचालय का ताला खुलते देखा ही नहीं गया।उनका आरोप है कि सफाईकर्मी कभी-कभार ही गांव में दिखते हैं,और शौचालय के संचालन को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाते।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि लाखों रुपए की लागत से बने इस शौचालय की हालत दिनबदिन बिगड़ती जा रही है। देखरेख के अभाव में भवन जर्जर हो रहा है, जिससे सरकारी धन की बर्बादी हो रही है।ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और स्वच्छ भारत मिशन से इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी मांग की है,कि शौचालय को तत्काल खोला जाए,नियमित सफाई और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए,ताकि ग्रामीणों को खुले में शौच से मुक्ति मिल सके।

बाजे-गाजे के साथ श्रीराम की बारात मिथिला पहुंची-नगर सजा, हृदय सजे, और देव- मानव सभी आर्नादित हो उठे। मांडवी संग भरत, उर्मिला संग लक्ष्मण और श्रुतकीर्ति संग शत्रुघ्न के विवाह प्रसंगों ने कथा को पूर्णता दी। जब जानकी जी की विदाई का क्षण आया, तो पांडाल में सनटाटा छग गया। श्रद्धालुओं की आंखों से अश्रुधारा बह निकली-मानो अपनी ही बेटी की विदाई देख रहे हों।

शास्त्री शाकाम्भरी द्विवेदी ने बताया कि उस समय केवल मिथिला वासी ही नहीं, पशु-पक्षी तक विलाप करने लगे; जनकनंदिनी की विदाई ने समूची मिथिला को करुणा में डुबो दिया। कथा के बीच शास्त्री जी ने परशुराम-लक्ष्मण संवाद का विस्तार से वर्णन करते हुए जीवन का अमूल्य संदेश दिया। शिवधनुष भंग के पश्चात भगवान परशुराम के क्रोध से भरे मिथिला आगमन का प्रसंग सुनाते हुए उन्होंने समझाया कि क्रोध पर नियंत्रण और मधुर वाणी ही सच्ची शक्ति है-जो काम तलवार



नहीं कर पाती, वह काम वाणी कर देती है। श्रीराम का संयम और लक्ष्मण की विनोदपूर्ण वाणी, दोनों मिलकर धर्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

इस भक्तिरस से ओतप्रोत संध्या में मुख्य यजमान उमेश मिश्रा, गौरव मिश्रा, सौरभ मिश्रा, छैल बिहारी दास मानस केसरी, शिवम द्विवेदी सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। संपूर्ण पांडाल में भक्ति की ऐसी अहिरल धारा बही कि करछना की यह रामकथा श्रद्धा, संस्कार और सद्भाव का अमिट संदेश छोड़ गई।

संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, मायके वालों का विरोध, पुलिस जांच में जुटी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज। थाना बारा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सीध-टिकट के मजरा पंडित का पूरा में बीती देर रात एक 32 वर्षीया विवाहिता को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।अचानक हुई इस घटना ने न केवल ससुराल पक्ष,बल्कि मायके वालों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है।मृतका के पीछे दो मासूम बेटियां भी हैं।उसकी पहचान सविता का रूप में हुई है,जिनका मायका कौंधियारा थाना क्षेत्र के मझियारी गांव में है। सविता के पिता शोभा पाल माझियारी गांव में रहते हैं। सविता का विवाह बारा थाना क्षेत्र

के सीध टिकट, मजरा पंडित का पुरवा निवासी संतोष पाल पुत्र मनीलाल पाल से हुआ था। दंपति की दो बेटियां हैं- (सुट्टि 5वर्ष)और शान्वी(3वर्ष)। मायके वालों का आरोप है कि सविता बीते 4 महीना से अपने मायके रह रही थी, और करीब 10 दिन पहले ही वह ससुराल आई थी।मंगलवार को ससुराल पक्ष की ओर से मायके में फोन कर सिर्फ इतना कहा गया कि, अचानक सविता की तबीयत बिगड़ गई है।इसके बाद ससुराल वालों से कोई संपर्क नहीं हो पाया और कुछ ही देर बाद सविता के मौत की सूचना मिली।जिससे मायके में कोहलाम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही डायल

112 पुलिस टीम पहुंची और प्रारंभिक जांच में जुट गई। पुलिस के मुताबिक, सविता को गंभीर हालत में इलाज के लिए स्वरूप रानी नेहरु चिकित्सालय, प्रयागराज ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देर रात तक घटनास्थल पर मायके पक्ष के लोग नहीं पहुंच पाए थे। थाना प्रभारी बारा विनोद सोनकर ने बताया कि सबको पंचायत नामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा यदि मायके पक्ष की ओर से कोई लिखित तहरीर प्राप्त होती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल, मौत के कारणों की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।

वां स्थान प्राप्त हुआ है। छात्रवृत्ति योजनाओ में प्राप्त आवेदनों का ससमय शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करने के निदेश जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया गया।विभिन्न पेंशन योजना यथा वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना व पेंशन एवं पीएम किसान निधि के लाभार्थियों की फैमिली आईडी इस माह के अंत तक बनवाये जाने के निर्देश समस्त सम्बंधित अधिकारियों को दिए गये। इसके अतिरिक्त जिला पंचायतराज अधिकारी, अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण तथा अधिशाषी अभियंता सिचाई खंड को अपने से सम्बंधित योजनाओं का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करते हुए प्रगति में सुधार लाये जाने के निर्देश दिए गए।

इसी प्रकार विकास भवन में जनपद में आधार अनुश्रवण समिति की वर्तमान त्रैमास की बैठक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित यूआईडीएआई के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 177 आधार किट क्रियाशील है जिनसे नवम्बर 2025 में 31105 आधार नामांकन/अपडेशन का कार्य किया गया। 0

से 05 वर्ष से कम आयु के आधार संतुषीकरण का मात्र 26 प्रतिशत एवं 05 से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का संतुषीकरण 91 प्रतिशत पाया गया जिस पर सीडीओ ने जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपेक्षित सुधार लाने हेतु निर्देशित किया।18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के 105 लम्बित आवेदनों का अविलम्ब निस्तारण हेतु ई0डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया।सीडीओ ने अन्य समस्त सम्बन्धित अधिकारी-अग्रणी बैंक मैनेजर, जिला प्रबन्धक बीएसएनएल, अधीक्षक प्रधान डाकघर, प्रबन्धक इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सीएससी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतापगढ़ को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष आधार किटों को क्रियाशील कराकर अधिक से अधिक आधार नामांकन/ अपडेशन कार्य कराना सुनिश्चित करें ताकि जनमानस को किसी प्रकार असुविधा न हो। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए दयाराम यादव, डीसी मनरेगा सन्तोष कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी केएन पाण्डेय, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रियंका सोनी, सभी कार्यवाही संस्था के अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, यूआईडीएआई के प्रतिनिधि व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

पथ दिखाई गई

अगर कहीं बाल विवाह हो रहा तो 1098-1090, 181 पर कॉल करके सूचित करने सूचना देने वाले का परिचय गोपनीय रखा जाएगा। इस एक छोटे से प्रयास से किसी बालिका का भविष्य अंधकारमय होने से बच सकता है। इस अवसर पर अशोक कुमार यादव, डा सेंटेंद्र मिश्र, सुनील पाण्डेय मनोज शर्मा, कैलाश चंद पाठक, राजेश यादव, सर्वेश उपाध्याय, राम दरस यादव राखेंद्र सिंह , अविनाश वर्मा, विजय प्रमोद पाण्डेय, अनिल चौबे, गणेश शुक्ल अनिल मिश्र, विंदेश पाण्डेय, राम उज्जाल पाण्डेय आदि रहे।

संक्षिप्त खबरें

कानपुर -प्रयागराज हाइवे पर बढ़ रहा हादसों का खतरा



घाटमपुर। कानपुर -प्रयागराज नेशनल हाईवे पर महाराज पुर थाना क्षेत्र स्थित ब्रम्ह देव मंदिर के पास अवैध वाहन पार्किंग बढ़े हादसों का न्योता दे रही है सदियों में घने कोहरे के कारण यहां सड़क दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ जाता है, जहां हर साल कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। मंदिर के पास सुबह से लेकर रात तक नेशनल हाईवे किनारे वाहनों की लंबी कतारें अवैध रूप से खड़ी रहती है,यह स्थान महाराज पुर में प्रमुख दुर्घटना बिंदु बन गया है, एक ओर जहां राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,, एनएचआई,, सड़क हादसों को रोकने के लिए रेडियम पट्टी लगाने और साइन बोर्ड लगाने जैसे प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इस अवैध पार्किंग पर उसकी नजर नहीं पड़ती, स्थानीय प्रशासन और खातायत पुलिस भी इस अवैध पार्किंग के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है,, इस संबंध में महाराज पुर इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि नेशनल हाईवे एनएच के महाराज पुर क्षेत्र के लिए एक स्पेशल क्रिटिकल कारिडोर टीम,सीसीटीम का गठन किया गया है उन्होंने आश्वासन दिया कि यह टीम हाइवे पर लगातार निगरानी कर रही है।

एडीजी आलोक सिंह ने डीजीपी की कांफ्रेंस में रखे विचार



कानपुर। माह दिसम्बर-2025 के अन्त में मुख्यमंत्री, उ०प्र० की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन प्रस्तावित है। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा/गोष्ठी की गयी। समीक्षा/गोष्ठी के दौरान आलोक सिंह, अवर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझावों को साझा किया गया।

रंजिश में हुई मारपीट में तीन पर केस हुआ दर्ज



लालगंज, प्रतापगढ़। मारपीट को लेकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लीलापुर थाना क्षेत्र के बहुचरा गांव निवासी किशोर कुमार वर्मा पुत्र स्व० रामेश्वर वर्मा ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि बीती पन्द्रह दिसंबर को पुरानी रंजिश को लेकर उसके भाई मनोज कुमार वर्मा व उसकी पत्नी कंचन वर्मा को गांव के मोती लाल वर्मा पुत्र अर्जुन वर्मा तथा मोती लाल वर्मा के पुत्रगण अंशू व प्रियांशु ने मारापीटा व जानलेवा धमकी दी। प्रभारी निरीक्षक मनोज पाण्डेय का कहना है कि जांच के बाद तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

बिस्कोहर में हिंदू सम्मेलन को लेकर हुआ भूमि पूजन

सिद्धार्थनगर । जिले के बिस्कोहर कस्बे के प्राइवेट बस अड्डे के पास स्थित एक निजी विद्यालय में 21 दिसंबर को होने वाले हिंदू सम्मेलन के आयोजन को लेकर बुधवार को विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। आचार्य ब्रजेश पाठक द्वारा प्रस्तुत वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच वरिष्ठ समाजसेवी सुधीर त्रिपाठी ने भूमि पूजन प्रक्रिया कार्यक्रम संपन्न किया। इस अवसर पर खंड कार्यवाह अजय, खण्ड प्रचारक ऋतुराज कपल, सुधीर त्रिपाठी, संजय सिंह, मोना पाण्डेय, मारुति नन्दन मौर्या, सचिन गुप्ता, रामशंकर यादव, रामदास मौर्या, अनिल तिवारी, आयुष मोदनवाल, दयानन्द शुक्ला, विवेक गुप्ता, किशन पासवान, रोहित गुप्ता, प्रिंस भारत, मंतोष पाठक, साजन सिंह, गुलाब पाण्डेय आदि मौजूद रहे।

सरकारी धन का दुरुपयोग या भू-माफिया को संरक्षण? पार्क के हरित क्षेत्र को नष्ट करने पर शासन से शिकायत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) साहित्य प्रचार विभाग के जिला संयोजक, प्रकाश वीर आर्य ने गोविंद नगर, ब्लॉक-8 स्थित सार्वजनिक पार्क में बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण और हरित क्षेत्र के विनाश को लेकर जिलाधिकारी कानपुर नगर, नगर आयुक्त नगर निगम और मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार से तत्काल और कठोर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पार्क के 70% हरित क्षेत्र को जानबूझकर इंटरलॉकिंग टाइल्स से पाट दिया गया है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के स्पष्ट आदेशों की खुली अवमानना है।

मुख्य आरोप और चौंकाने वाले तथ्य: हरित क्षेत्र का विनाश: शिकायतकर्ता के अनुसार, पार्क के लगभग 70% हरित क्षेत्र (घास और पुराने पौधे) को अवैध रूप से इंटरलॉकिंग टाइल्स से पाट दिया गया है। NGT के आदेशानुसार, पार्कों में केवल वॉकिंग ट्रैक (अधिकतम 5% क्षेत्रफल) ही पक्का किया जा सकता है। अवैध



धार्मिक/पक्के निर्माण: पार्क के हरित क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व एक 10x20 फीट का धार्मिक चबूतरा बना दिया गया था, जिसे नगर निगम के अधिकारियों ने 'पुराना निर्माण' बताकर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण आज पार्क में हरियाली की जगह कब्जे के बड़े-बड़े ढांचे खड़े हो गए हैं। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग: शिकायत में आरोप है कि इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य सार्वजनिक धन (विधायक/सांसद निधि, आदि) का दुरुपयोग है, जिसका सीधा उद्देश्य हरित क्षेत्र को 'ऑक्सीजन ज़ोन' से हटाकर अवैध निर्माण को संरक्षण देना प्रतीत होता है। यह धारा 324 BNS के अंतर्गत (घास और पुराने पौधे) को अवैध रूप से हटाना और ज़रूरतमंदों को गरीबों व असहायों को गर्म कपड़े व कम्बल आदि देकर उन्हें भी ठंड से राहत पहुंचाने में अपना

कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को चिलबिला, महली, सदर बाजार आदि गली कूचे और चौराहों पर गाय तथा बछड़ों को पकड़कर बोरे तथा बोरे के कोट पहनाया गया। रेशनलाल उमरवैश्य ने कहा कि पशुओं के संरक्षण के इस अभियान में सहयोग दे। सभी जनमानस से अपील है कि अपने घरों व गांव में घुमंतू पशुओं को इस भीषण ठंड में बचाने के लिए बोरे के कोट पहनाएं और ज़रूरतमंदों को गरीबों व असहायों को गर्म कपड़े व कम्बल आदि देकर उन्हें भी ठंड से राहत पहुंचाने में अपना

बेजुबान जानवरों को भीषण ठंड से बचाने के लिए एलायंस क्लब पहना रहा बोरे के कोट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रतापगढ़। एलायंस क्लब इंटरनेशनल प्रतापगढ़ द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भीषण सर्दी को देखते हुए बेसहारा पशुओं के संरक्षण का अभियान चलाया जा रहा है। सड़क पर लावारिस घूमते हुए गाय, बछड़े तथा भैंस इत्यादि को बोरे के कोट और बोरे का वस्त्र क्लब के अंतरराष्ट्रीय डायरेक्टर रेशनलाल उमरवैश्य की अगुवाई में पहना कर संरक्षित किया जा रहा है। जल, चारे तथा गुड़ इत्यादि की व्यवस्था भी क्लब की टीम

योगदान दें और पूण्य के भागीदार बने। धरती पर पशुओं को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना मनुष्यों को। मनुष्य तो अपनी व्यथा बताकर अपनी जरूरत पूरी कर लेता है। लेकिन इन बेजुबान जानवरों को हम सब का कर्तव्य बनता है कि उनका भी ध्यान अपने जैसा रखें। अभियान में सुरेश अग्रवाल, छेदीलाल, देवानंद, संतोष कुमार, संजय कनौजिया, आदर्श उमरवैश्य, विवेक यादव, दयाराम मौर्य, देवेंद्र कुमार, अनवर, शिवेश शुक्ला, परमानंद मिश्रा, अमन गुप्ता, शिवम खंडेलवाल इत्यादि शामिल रहे।

नगर निगम सड़कों के गड्ढे कागज पर बंद कर रही पार्कों की जमीन गेस्ट हाउस बनाने के लिए बाहरी समितियों को दे रही

●7 जनवरी 2026 से सपा की आंदोलन की तैयारी की जाएगी-हाजी फजल महमूद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर। बुधवार समाजवादी पार्टी के 78 वार्डों के प्रमुख पीडीए टीम एवं संयुक्त सर्वेक्षण टीम की बैठक सपा महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद की अध्यक्षता में दिन में 3:00 बजे आरंभ हुई। बैठक को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने कहा कि कैंट गोविंद नगर सीसमऊ आर्य नगर किडवई नगर क्षेत्र के 300 मलिन बस्तियों में पानी तथा सफाई की कोई सुविधा नहीं है इसके अलावा 78 वार्डों के क्षेत्रों नगर निगम सड़कों के गड्ढे कागजों पर

भरवा है भौतिक मरम्मत व गड्ढे भरवाने में नगर निगम पीछे रही है जिसकी आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं अभी हाल में एक लड़का गड्ढे और मिट्टी के ढेर के कारण दुर्घटना में मर जाने से उसके परिवार में कोहलम मचा है। महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कानपुर हाजी फजल महमूद ने आगे कहा कि गंदगी के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है इसकी वजह से हृदय रोगियों की संख्या डॉक्टर के यहां बढ़ती जा रही है लेकिन नगर निगम की मेयर साहिबा पाकों एवं गेस्ट हाउस के चक्कर में पड़ी हैं महानगर अध्यक्ष ने वक्तव्य में कहा कि नगर निगम स्वयं बुजेंद्र स्वरूप पार्क में गेस्ट हाउस बनाने में सक्षम है लेकिन मेयर इशारे एक निजी घराने को गेस्ट हाउस बनाने वह मालिकाना हक देकर शहर की जनता के साथ खिलवाड़ कर नगर निगम द्वारा परियोजनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं महानगर अध्यक्ष हाजी

एड्स नियंत्रण हेतु जनपद स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अधीन संचालित यूनिट सम्पूर्ण सुरक्षा केंद्र के माध्यम से कलेक्ट्रेट सभागार में उन्मुखीकरण कार्यशाला सम्पन्न हुआ। इस उन्मुखीकरण कार्यशाला का शुभारम्भ जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य विकास अधिकारी, कमांडेंट होम गार्ड जिला आबकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा बस्ती मंडल से अखिलेश सिंह क्लस्टर प्रोग्राम मैनेजर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम से पंकज त्रिपाठी जिला कार्यक्रम समन्वयक, सतीश मिश्रा, उस्मान अली, एसएसके यूनिट, ए.आर.टी.यूनिट एसटीआई यूनिट समस्त आईसीटीसी एलटी समस्त परामर्शदाता उपस्थित रहे । राष्ट्रीय

मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन को लेकर हुई बैठक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर। उसका बाजार कस्बा अंतर्गत स्थित प्राचीन शिवमंदिर के परिसर में बुधवार को आचार्य संतोष श्री महाराज के अगुवाई में बैठक हुई। बैठक में आगामी जनवरी एवं फरवरी माह में होने वाले मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह की रूपरेखा बनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों से बातचीत करते हुए आचार्य संतोष

यह कार्य न केवल प्रशासन को गुमराह करने का, बल्कि दोषी अधिकारियों को बचाने का भी स्पष्ट प्रयास है।

तत्काल कार्रवाई की मांग: भाजपा नेता ने मांग की है कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई और IPC/BNS की सुसंगत धाराओं के तहत तत्काल प्रार्थमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया जाए। उन्होंने 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की मांग की है: तत्काल ध्वस्तिकरण और बहाली: पार्क में मौजूद अवैध धार्मिक निर्माण और नए इंटरलॉकिंग टाइल्स को हटाकर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 70% हरित क्षेत्र को पार्क के मूल रूप में तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। कार्रवाई का विवरण: की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण और अवैध निर्माण हटाने की समय-सीमा 7 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाए। आर्य ने चेतावनी दी है कि यदि इस अत्यंत गंभीर शिकायत पर नियमानुसार और कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वह पूरे प्रकरण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर करने के लिए बाध्य होंगे।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में नया नाम जुड़वाने का मौका, 26 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे फॉर्म-6

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत मतदाता सूची के शुद्धीकरण और अद्यतन का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान में ऐसे सभी पात्र नागरिक, जिनकी आयु एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या होने वाली है और जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्थानांतरित होकर जनपद में आए नागरिक, जिनका नाम पूर्व निवास स्थान की मतदाता सूची में था, अथवा जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया, वे भी फॉर्म-6 भरकर इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। आवेदन भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in तथा वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से ऑनलाइन या

संबंधित बृथ लेवल अधिकारी के पास ऑफलाइन किया जा सकता है। फॉर्म-6 जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर निर्धारित की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फॉर्म-6 के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा की अंकपत्र, पासपोर्ट अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण मान्य होंगे। निवास प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली या पानी का बिल, बैंक पासबुक, पासपोर्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा।

फोटो पहचान के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र संलग्न किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपील की कि सभी पात्र नागरिक समय-सीमा के भीतर आवेदन कर आवश्यक

बिधनू क्षेत्र में माइनर की सफाई नहीं, 10 बीघा की फसल जलमग्न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

घाटमपुर। कानपुर नगर के खंड विकास बिधनू क्षेत्र स्थित मटियारा गांव में नहर माइनर की अघूरी सफाई के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, रामगंगा नहर से पानी छोड़े जाने के बाद माइनर ओवर फ्लो हो गया, जिससे करीब दस बीघे गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। किसानों का आरोप है कि इससे पहले धान की फसल भी इसी माइनर के पानी से बर्बाद हो चुकी है, ग्रामीणों के अनुसार धान की फसल बर्बाद होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल शिकायत दर्ज कराई थी,इस पर नहर विभाग ने अक्टूबर माह में माइनर की सफाई की, हालांकि किसानों का कहना है कि जमीनी स्तर पर सफाई अघूरी है, जिससे एक बार फिर से खेतों में पानी भर गया। ग्राम प्रधान राहुल चतुर्वेदी ने नहर विभाग पर कागजों में ही माइनर की सफाई दिखावों का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि माइनर किनारे की पटरी पर चलना मुश्किल हो गया है,धान



के बाद अब गेहूं की फसल भी डूब गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको बताते चलें कि मटियारा गांव निवासी रामवती बाजपेई ने बताया कि उनके ढाई बीघा खेत में धान के बाद अब गेहूं की फसल डूब गई, उन्होंने बताया कि 80 रुपये किलो बीज बोया था, नहर वालों ने सब बर्बाद कर दिया, नहर विभाग की कथित लापरवाही के कारण, उमेश बाजपेई, मिथुन पांडेय, वीरेंद्र पांडेय, ब्रजेश कुमार, मुनीलाल और हरविलास सहित कई किसानों के करीब दस बीघा, खेत जलमग्न हो गए, किसानों ने प्रशासन से जल्द पानी निकासी और माइनर की समुचित सफाई करमें की मांग की है।

कृषि विज्ञान केंद्र ऐंटू कलाकांकर में किसान दिवस का आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रतापगढ़। जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र ऐंटू कलाकांकर में किसान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 80 कृषकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान कृषक नरेंद्र कुमार गौतम निवासी ग्राम सहबाद द्वारा लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाभ न मिल पाने, कृषक शिवबहादुर यादव द्वारा किसान पंजीकरण में ग्राम एवं ब्लॉक का गलत फीड हो जाने एवं कृषक नरेंद्र सेन मौर्य, राम सुनेर पटेल, राम दुलारे (कृषि सोनमऊ), सुरेश यादव निवासी त्रिलोचनपुर द्वारा छुट्टा पशुओं तथा आम की बागवानी को नीलगाय से बचाने हेतु ताराबाड़ (फेंसिंग) की मांग रखी गई। ग्राम साहाबाद के कृषकों



द्वारा चकबंदी कराए जाने की मांग की गई। सतीश मौर्य द्वारा डेयरी उद्योग प्रारंभ करने हेतु जानकारी चाही गई। मोहम्मद राजा निवासी मुरस्सापुर द्वारा बकरी पालन योजना से संबंधित जानकारी मांगी गई। भूमि संरक्षण अधिकारी चमन सिंह द्वारा सभी कृषकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबोधित विभागों को निस्तारण हेतु अवगत कराया गया। इस अवसर पर उपस्थित

जागरूकता ही एड्स से बचाव : डीएम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर। एचआईवी-एड्स के प्रसार पर प्राभावी नियंत्रण और समय पर जांच व उपचार को मजबूत करने के उद्देश्य से मंगलवार को कलेक्ट्रेट में ‘सुरक्षा से सम्पूर्ण सुरक्षा तक’ कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तरीय एडबोकेसी बैठक व संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने की। जिलाधिकारी ने कहा कि जागरूकता ही एड्स से बचाव का सबसे प्राभावी माध्यम है। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और एचआईवी से जुड़ी सही जानकारी आमजन तक पहुंचाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि जांच, परामर्श और उपचार की सुविधाओं के प्रति लोगों का धरोसा बढ़ाया जाए तथा समाज में व्याप्त लांछन और भेदभाव को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं।



कार्यशाला का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. हरिदत्त नेमी एवं जिला क्षयरोग अधिकारी डा. सुबोध प्रकाश के नेतृत्व में किया गया। बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे। जिला क्षयरोग अधिकारी डा. सुबोध प्रकाश ने सुरक्षित व्यवहार अपनाने पर जोर देते हुए बताया कि समय पर जांच और नियमित उपचार से एचआईवी-एड्स को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने 95-

दस्तावेजों के साथ प्रक्रिया पूर्ण करें, जिससे उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो। एसआईआर के अंतर्गत 12,957 फॉर्म-6 हो चुके हैं जमा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत नए मतदाता बनने के लिए अब तक कुल 12,957 फॉर्म-6 जमा किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ के पास पर्याप्त मात्रा में फॉर्म-6 उपलब्ध है और मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से 3,082, कानपुर कैंट से 3,685, घाटमपुर से 1,701, सीसामऊ से 1,556, बिल्हौर से 1,171, किदवई नगर से 196, आर्य नगर से 690, गोविंद नगर से 448, कल्याणपुर से 128 तथा बिठूर विधानसभा क्षेत्र से 300 फॉर्म-6 प्राप्त हुए हैं।

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम राीण गया ज्ञापन

औराई विधानसभा क्षेत्र, जनपद भदोही में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के औराई तहसील महामंत्री नेहाल अली के नेतृत्व में पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण को लेकर माननीय विधायक दीनानाथ भास्कर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पंजीकृत पत्रकार संघन है, जो प्रदेश के 18 मंडलों, 75 जनपदों एवं 551 तहसीलों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। बावजूद इसके, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत रिट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को सस्कारी सुविधाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से तहसील स्तर पर पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने, पत्रकार हितों की रक्षा हेतु स्थाई समितियों के गठन, ग्रामीण पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड एवं निःशुल्क बस यात्रा सुविधा, प्रदेश स्तरीय मान्यता व विज्ञापन समितियों में प्रतिनिधित्व, लखनऊ में संगठन के लिए निःशुल्क कार्यालय, ग्रामीण पत्रकार आयोग के गठन तथा पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करने से पूर्व सख्त अधिकारी से जांच करने जैसी प्रमुख मांगें रखी गई। विधायक दीनानाथ भास्कर ने पत्रकारों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री तक ज्ञापन पहुंचाने का आश्वासन दिया।

समस्त विभागीय अधिकारियों द्वारा सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी कृषकों को दी गई। समस्त कृषकों को फॉर्मर रजिस्ट्री करने के लिए बताया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नवीन सिंह द्वारा कृषकों को नई कृषि तकनीकों एवं नवाचरण के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया। किसान दिवस कार्यक्रम में भूमि संरक्षण अधिकारी चमन सिंह, जिला उद्यान अधिकारी सुनील कुमार शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नवीन सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक अभियंता (लघु सिंचाई/नलकूप), अधिशासी अभियंता (विद्युत विभाग), एडीसीओ, सक्कारिता सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

बाल विवाह मुक्त भारत के लिए शपथ दिलाई गई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के उसका बाजार कस्बा के किसान इंटर कालेज पर बुधवार को बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य संजय कुमार गुप्ता ने सभी को बाल विवाह मुक्त भारत के लिए शपथ दिलाई। प्रधानाचार्य ने बच्चों को बाल विवाह से होने वाले समस्याओं के बारे में बताया । उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक गैर कानूनी कार्य है। इसी कारण सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का प्रावधान



किया है। इसमें बाल विवाह करने एवं कराने वाले सभी लोगों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। सविधान में बताया गया है कि विवाह की आयु लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। बालिकाओं और बालकों को बताया गया कि

अगर कहीं बाल विवाह हो रहा तो 1098, 1090, 181 पर कॉल करके सूचित करें। सूचना देने वाले का परिचय गोपनीय रखा जाएगा। इस एक छोटे से प्रयास से किसी बालिका का भविष्य अधकारमय होने से बच सकता है। इस अवसर पर अशोक कुमार यादव, डा सतेंद्र मिश्र, सुनील पाण्डेय, मनोज शर्मा, कैलाश चंद पाठक, राजेश यादव, सविश उपाध्याय,राम दर्मा यादव, रावबेंद्र सिंह , अविनाश वर्मा, विजय , प्रमोद पाण्डेय, अनिल चौबे, गणेश शुक्ल, अनिल मिश्र, विरेंद्र पाण्डेय, राम उजागिर पाण्डेय आदि रहे।

